स्थानों (एमएडीए पाकेट) और समुदायों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस समय, 193 आईटीडीपी, 249 एमएडीए पाकेट, जनजातीय केंद्रीकरण के 17 समूह और 74 आदिम जनजातीय समूह परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। जनजातीय उपयोजना की नीति आठवीं योजना के दौरान जारी रहेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक और ठोस लाभ लक्ष्य तक पहुंचे, इसे आयोजना का एक प्रभावी उपकरण बनाने के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी।

Welfare Scheme in Rural Areas for the Urban Poor

1836. fHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleasad to state;

(a) whether 't is a fact that a large number of Ministries have their separate eprogrammes for funding of voluntary agencies engaged in implementation of welfare schemes in rural areas and for the arban poor; and

(b) if so, the details of the amount spent by each Ministry during the last three years through voluntary agencies and the criteria laid down therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) Details are being collected and will be laid on the Table of the House.

Areas covered by Integrated Rural Energy Planning

1837. SHRIMATI KAMLA SINHA; Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state the deatils of areas which are covered by the Integrated Rural Energy Planning and what further extension of this programme are intended by Government in the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENER_ GY SOURCES (SHRI SUKH RAM): Tho Integrated Rural Energy Plannng Programme is being taken up in selected blocks in all States and UTs except Chandigarh. Up to 1991-92, 252 blocks have been covered under this programme. The) Statewise break up of the blocks covered under the programme is given in the attached statement. (See below) The Programme involved setting up of project cells in the selected blocks which would prepare and monitor the implementation of the block level IREP Projects. It is proposed to extend the programme at the; rate of about 100 blocks a year in the 8th Plan. The details of the programme in the 8th Plan are being worked out.

Statement

Statewise break up of the Blocks covered under IREP Programme

Name of State|UTs	No. of IREP Blocks
Andhra Pradesh	8 (Mandals)
Arunachal Pradesh	4
Assam	10
Bihar	7
Goa	4
Gujarat	15
Haryana	*14*
Himachal Pradesh	17
Jammu & Kashmir	5
Karnataka	9
Kerala	8
Madhya Pradesh	21
Maharashtra	13
Manipur	4
Meghalaya	6
Mizoram	3
Nagaland	2
Orissa	5
Punjab	8
Rajasthan	7
Sikkim	3
Tamil Nadu	11
Tripura	5
Uttar Pradesh	48
West Bengal	7
(i) TOTAL State;	239

Name of State /UTs	No. of IREP Blocks
A N Islands	3
Chandigarh	1
Dadra & Nagar Haveli	1
Daman & Diu	1
Delhi	5
Lakhadweep	1
Pondicherry	2
(ii) TOTAL UTs;	13
GRAND TOTAL (i) and (ii):	252

सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में गिरावट के कारण

1838. **श्री अजीत जोगी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में गिरावट आने के क्या कारण हैं ;

(ख) घरेलू और गैर सरकारी निगमित क्षेत्र की बचतों में वृद्धि की तुलना में सरकारी क्षेत्र की बचतों में तेजी से गिरावट आने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में वर्ष 1990-91 में 5.6% की वृद्धि 1980 के दशक के दौरान देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसमें औसत मिश्रित संवृद्धि 5.6% दर्ज की गई थी। सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि, पिछले वर्ष (1989 90) में, जब सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि 6% थी, औसत संवृद्धि से अधिक होने के कारण वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 में कम रही।

(ख) यह कमी, मुख्यत: सरकारी बचतों की खराब स्थिति के कारण रही है। फलत: सरकारी राजस्व की तुलना में सरकारी व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई।

(ग) सरकार ने व्यय में कमी करने तथा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के अनेकों उपाय किए हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के उपायों में शामिल हैं, इमदादों में कटौती, अन्य व्ययों में कटौती करके अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान को आत्मसात करना, सार्वजनिक ऋण तथा ब्याज भुगतानों आदि में कमी लाकर बजट घाटे को कम करना। राजस्व बढ़ाने के उपायों में प्रत्यक्ष कर आधार को व्यापक बनाना तथा अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाना, शामिल है।

गुजरात में योजनाओं की प्रगति पर निगरानी

1839. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार गुजरात में लागू की जा रही योजनाओं की प्रगति पर निगरानी नहीं रख रही है ; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात में उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी निगरानी केंद्रीय सरकार ने अपनी ही पहल पर की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) जी, नहीं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रत्येक 20 करोड रुपए तथा इससे अधिक लागत वाली केंद्रीय परियोजनाओं का प्रबोधन किया जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार गुजरात में केन्द्रीय परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।